पूरी बेंच

एम. ए.एल. पुंछी, वजागर सिंह अमी ए. पी. चौधरी, जे.जे. के समक्ष

राज इंदर गिल.-याचिकाकर्ता.

बनाम

देव समाज परिषद सोसायटी और अन्य,-प्रतिवादी।

1985 की सिविल रिट याचिका संख्या 99।

फरवरी 28-1989

पंजाब संबद्ध कॉलेज (कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा) अधिनियम (1974 का XXIII)–धारा 4(4)–पंजाब न्यायालय अधिनियम (1918 का VI)–धारा 18(1) 20, 21 और 21-4–सामान्य खंड अधिनियम (1897 का एक्स) - धारा 2(15) - धारा 4(4) जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील का प्रावधान करती है - अपील का निर्णय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाता है - अतिरिक्त जिला न्यायाधीश: क्या अपील पर निर्णय लेने में सक्षम है - क्या 'जिला न्यायाधीश' में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश शामिल हैं .

यह माना गया कि यह जिला न्यायाधीश का न्यायालय है जो अपीलीय मंच है और इस तरह यह अपील प्राप्त करता है, न कि जिला न्यायाधीश या व्यक्तिगत रूप से जिला न्यायाधीश में कोई व्यक्तित्व पदनाम। एक बार जब अपील पर विचार किया जाता है और जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो यह अनिवार्य रूप से इसका मतलब है कि जिला न्यायाधीश को न केवल निपटान के लिए अपील को अपने पास रखने का अधिकार है, बल्कि पंजाब न्यायालय अधिनियम 1918 की धारा 21 के तहत अपने न्यायालय में न्यायाधिकार का प्रयोग करने के लिए राज्य द्वारा नियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को भी सौंपने का अधिकार है। .

और उस अपील के निपटारे से निपटने के दौरान अतिरिक्त न्यायाधीश को अपील सौंपने पर जिला न्यायाधीश का न्यायालय माना जाएगा, जो अपील के लिए जिला न्यायाधीश के समान ही अच्छा है।

(पैरा 12, 13)

माना गया कि पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 20 और 21 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने से बचने के लिए एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और व्याख्या की जानी चाहिए। अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि विधानमंडल केवल जिला न्यायाधीश के व्यक्ति में अपीलीय मंच प्रदान करने में उत्साही था। वास्तव में अपीलीय मंच जिला न्यायाधीश के न्यायालय में प्रदान किया गया था, जिसका अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एक अभिन्न अंग है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय, किसी भी स्थिति में, जिला न्यायाधीश

द्वारा दिए गए निर्णय की तुलना में गुणवत्ता और प्रभावकारिता में कम नहीं कहा जा सकता है। हमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को हटाने के लिए अधिनियम में कोई सामग्री नहीं मिलती है, खासकर जब पुनियाब न्यायालय अधिनियम न्यायिक शर्तों में नहीं है, तो ऐसा भेदभाव पैदा होता है।'

(पैरा 16).

पर आयोजित: -

(ए) अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पंजाब संबद्ध कॉलेज (कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा) 1974 की धारा 4 की उप-धारा (4) के तहत अपील पर निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं, यदि अपील उनके द्वारा की जाती है। निपटाए जाने और निपटारे के लिए न्यायाधीश। और यह क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न का हमारा उत्तर है;

(बी) कि सबसे पहले जिला न्यायाधीश का व्यक्ति और फिर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश/न्यायाधीशों को, उनके न्यायालय में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया जाता है, ऐसे अदालती कार्यों के लिए जो केवल उन्हें या उन्हें सौंपे जाते हैं और उनके या उनके द्वारा निपटाए गए मामले को उचित रूप से निपटाते हैं। जिला न्यायाधीश के न्यायालय के रूप में। यह न्यायिक प्रभावकारिता के लिए है न कि दूसरा जिला न्यायाधीश बनाने के लिए। यह सहायक प्रश्न का हमारा उत्तर है; और

(सी) पहले दर्ज किए गए कारणों के लिए, हम प्रबंध समिति के मामले में व्यक्त किए गए विचारों को खारिज करते हैं और मंगई राम के मामले बहुत संकीर्ण हैं, जहां तक वे पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 20 और 21 की व्याख्या (प्रावधानों की व्याख्या करते समय) से संबंधित हैं 26)

1. प्रबंध समिति, गुरु गोबिंद सिंह गणतंत्र, जंडियाला बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 20 मई, 1980 को सिविल रिट याचिका संख्या 4337 में -

2. मंगई राम बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और ओजेजे 1977,

(यह मामला डिवीजन बेंच द्वारा बड़ी बेंच को भेजा गया था

इस मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए 3 सितंबर, 1987 को माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. सोढ़ी शामिल थे। माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति एम.एम. पुंची, माननीय श्रीमान् न्यायमूर्ति उजागर सिंह, माननीय श्रीमान् न्यायमूर्ति ए.पी.चौधरी ने कानून के प्रश्न का निर्णय लिया और मामले को 28 फरवरी को डिवीजन बेंच को वापस भेज दिया।

1989 कानून के अनुसार निपटान के लिए)।

एच. एल. सिब्बल, सीनियर. एच. एस के साथ वकील. तूर और डी.एस.अधिवक्ता- याचिकाकर्ताओं के लिए,

जे.एन.कौशल, और वरिष्ठ अधिवक्ता, और वी.के. बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कपूर और राजीव विज के साथ - प्रतिवादी के वकील।

निर्णय

व्लादन मोहन पंच, जे.-

(1) इस पूर्ण पीठ के समक्ष निर्णय की आवश्यकता वाला क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न यह है कि क्या एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पंजाब संबद्ध कॉलेज (कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के तहत अपील पर निर्णय लेने में सक्षम है। , 1974 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित)।

(2) उपरोक्त प्रश्न इस रिट याचिका में अनुबंध पी-12 के बाद से उठा है, इसमें लगाया गया आदेश अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा अधिनियम के पूर्वोक्त प्रावधान के तहत अपनी अपीलीय शक्तियों के कथित अभ्यास में पारित किया गया है। . मोशन बेंच ने इस मुद्दे पर न्यायिक राय के टकराव को देखते हुए सीधे रिट याचिका को डिवीजन बेंच में स्वीकार कर लिया। मामला जब डिवीजन बेंच के समक्ष रखा गया तो वही कठिनाई सामने आई। डिवीजन बेंच के समक्ष, इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के (प्रबंध समिति, गुरु गोबिंद सिंह रिपब्लिक कॉलेज, जंडियाला बनाम पंजाब राज्य और अन्य) (1) में दिए गए फैसले को याचिकाकर्ता द्वारा सेवा में रखा गया था। डिवीजन बेंच ने उक्त निर्णय की सत्यता पर संदेह व्यक्त किया। इन परिस्थितियों में, डिवीजन बेंच ने उक्त बिंदु को बड़ी बेंच के पास निर्णय के लिए भेज दिया। ऐसे में सवाल हमारे सामने है, जवाब मांग रहा है।

♦आवश्यक प्रोत्साहन देने के लिए मूलभूत तथ्य अभी भी आवश्यक होंगे। और वे ये हैं:

(3) जनवरी, 1982 में याचिकाकर्ता को देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चंडीगढ़ के प्रिंसिपल के रूप में चुना गया और नियुक्त किया गया, जो देव समाज काउंसिल सोसाइटी, प्रतिवादी नंबर 1 के प्रबंधन के तहत एक निजी तौर पर प्रबंधित कॉलेज है। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रबंधन प्रिंसिपल के रूप में उनके चयन से पहले उनसे दो कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए, ताकि जाहिर तौर पर उन्हें उचित समय पर उचित स्तर पर उपयोग में लाया जा सके। बाद में कभी-कभी, प्रबंध समिति के

कुछ सदस्यों के साथ उसका मतभेद हो गया और उन्होंने धमकी दी कि वे अपने पास मौजूद खाली कागजों का इस्तेमाल कर लेंगे। प्रबंध समिति के कुछ सदस्यों की धमकी के तहत, उन्होंने अप्रैल 1983 में अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे प्रबंधन ने 23 अप्रैल, 1983 को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने खाली कागजात वापस करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें दूसरा प्राप्त करने के बाद वापस कर दिया गया। लिखना3 याचिकाकर्ता से कि उसने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है, उसने फिर अधिनियम के प्रावधान का संरक्षण लेना चुना। 31 मई, 1983 को, उन्होंने सार्वजनिक शिक्षा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के निदेशक के अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का इस्तीफा स्वेच्छा से नहीं था और अधिनियम की धारा 3 और 4 के प्रावधानों का पालन किए बिना था, धारा 3 घरेलू जांच पर विचार करती है और धारा 4 डालती है। कर्मचारियों को हटाने और बर्खास्त करने पर एक कारक जब तक कि इसे सार्वजनिक निर्देश निदेशक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो। इस अधिकारी ने याचिकाकर्ता और प्रबंधन को सुनने के बाद याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार कर लिया और 14 फरवरी, 1984 को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को प्रिंसिपल का पद धारण करने वाला माना जाए, जिससे वह सेवाओं आदि के सभी लाभों का हकदार हो। संख्या एक और प्रबंध समिति प्रतिवादी संख्या दो ने सार्वजनिक निर्देश निदेशक के आदेश के खिलाफ जिला न्यायाधीश चंडीगढ़ के समक्ष अपील दायर की, अपील जिला न्यायाधीश द्वारा श्री ओपी गुप्ता अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ के समक्ष की गई, जिन्होंने शक्ति का कथित प्रयोग किया था। अधिनियम की धारा 4 (4) के तहत अपील को स्वीकार कर लिया गया और सार्वजनिक निर्देश के निदेशक के आदेश को खारिज कर दिया गया, व्यापक आदेश दिनांक 12 दिसंबर, 1984। परिशिष्ट पी 12 याचिकाकर्ता के इस्तीफे के बारे में प्रबंधन की दलील स्वैच्छिक होने के कारण अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा स्वीकार कर ली गई है। . अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ के आदेश को रिट याचिका में चुनौती दी गई है। हमें इस फैसले पर प्रतिवादी की तथ्यात्मक दलीलों का बोझ डालने की जरूरत नहीं है

(4) अब, यह 'जिला न्यायाधीश' कौन है जो अधिनियम की योजना में अपीलीय मंच के रूप में प्रमुखता से शामिल है? एक व्यक्तित्व पदनाम या एक न्यायालय? हालाँकि याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री हीरा लाल सिब्बल ने सीधे तौर पर स्वीकार किया कि वह एक न्यायालय हैं और कोई व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन केवल उनकी रियायत से प्रश्न का समाधान नहीं होगा। इसे अभी भी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की सहायता से हल करना होगा।

मूल क्षेत्राधिकार के एक प्रमुख सिविल न्यायालय के न्यायाधीश; लेकिन इसमें उच्च न्यायालय को उसके सामान्य या असाधारण मूल नागरिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में शामिल किया जाएगा। पंजाब जनरल क्लॉज एक्ट में 'जिला' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, अभिव्यक्ति 'जिला न्यायाधीश' यह खुलासा करती है कि उक्त न्यायाधीश मूल क्षेत्राधिकार के एक प्रमुख सिविल न्यायालय का है। और उस न्यायालय और उसके अधिकार क्षेत्र की खोज के लिए, किसी को पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 पर जाना होगा।

इसकी धारा 18(1), जो अध्याय-एचटी में आती है, सिविल न्यायालयों का वर्गीकरण प्रदान करती है और जिला न्यायाधीश का न्यायालय ऐसे वर्गीकृत न्यायालयों में से पहला है। 1963 के पंजाब अधिनियम संख्या 35 के अधिनियमन से पहले अतिरिक्त न्यायाधीश का न्यायालय ऐसे वर्गीकृत न्यायालयों में दूसरा था। लेकिन उक्त अधिनियम में इस तरह के वर्गीकरण को छोड़ दिया गया। अध्याय III के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, धारा 19 विशेष रूप से राज्य सरकार को अपने प्रशासन के तहत राज्य के क्षेत्रों को नागरिक जिलों में विभाजित करने का आदेश देती है, इन जिलों की सीमा या संख्या को बदलने की शक्ति को संरक्षित करती है। इस तरह एक जिला बनता है. धारा 20 राज्य सरकार को निर्देश देती है कि वह उतने व्यक्तियों को नियुक्त करे जितने वह जिला न्यायाधीश के रूप में आवश्यक समझे, और प्रत्येक जिले में एक ऐसे व्यक्ति को उस जिले के जिला न्यायाधीश के रूप में तैनात करेगी। इसके प्रावधान के तहत, यदि राज्य सरकार उचित समझे तो एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक जिलों का जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। धारा 19 और 20 का संयुक्त वाचन हमें एक जिले के निर्माण और उस जिले के जिला न्यायाधीश के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति की प्रक्रिया बताता है। इसलिए पंजाब संबद्ध कॉलेज (कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1974 को अधिनियमित करते समय, और जिस जिले में संबद्ध कॉलेज स्थित है, वहां एक जिला न्यायाधीश के अस्तित्व को मानते हुए, और एक अपीलीय मंच का निर्माण करते समय विधानमंडल को अवश्य ही ऐसा करना चाहिए। पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 19 और 20 के तहत सिविल जिलों और जिला न्यायाधीशों के निर्माण का संज्ञान माना जाता है। अब तक कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई है। यह कि जिला न्यायाधीश एक प्रमुख सिविल न्यायालय या मूल क्षेत्राधिकार का न्यायाधीश है, इससे भी कोई कठिनाई नहीं होती है। श्री सिब्बल की यह रियायत कि अधिनियम की धारा 2(सी) में संदर्भित जिला न्यायाधीश ही जिला न्यायाधीश का न्यायालय है, स्पष्ट रूप से सही है, क्योंकि यह कानून का सही कथन है जैसा कि बाद के पैराग्राफों में धीरे-धीरे स्पष्ट हो जाएगा।

(6) अब अनुभागों का एक और जोड़ा ध्यान देने योग्य है। और ये दोनों पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 21 और 21-ए हैं, जिन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

“21. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-

(1) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, नियुक्ति भी कर सकती है

अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को जिला न्यायाधीशों के क्षेत्राधिकार या अधिक न्यायालयों का प्रयोग करना होगा।

(2) अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को केवल ऐसे मामलों से निपटने और निपटाने का अधिकार क्षेत्र होगा क्योंकि उच्च न्यायालय सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उन्हें निपटाने और निपटाने का निर्देश दे सकता है या जिले के जिला न्यायाधीश उन्हें निपटाने और निपटाने के लिए सौंप सकते हैं। :

बशर्ते कि 28 जून, 1963 से ठीक पहले अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के पास लंबित मामलों को उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाने या निपटाने के लिए निर्देशित या जिले के जिला न्यायाधीश द्वारा उन्हें सौंपे गए मामले माना जाएगा। .

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट मामलों से निपटने और निपटाने के दौरान, एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश का न्यायालय माना जाएगा।

21-ए. जिला न्यायाधीश के कार्यों का अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को सौंपना.–उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश के किसी भी कार्य को सौंप सकता है, जिसमें मामलों और अपीलों को प्राप्त करने और पंजीकृत करने के कार्य भी शामिल हैं।

कार्यों के ऐसे असाइनमेंट के लिए जिला न्यायाधीश के न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, और उन कार्यों के निर्वहन में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अधिनियम में किसी भी बात के बावजूद, जिला न्यायाधीश के समान शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

7. धारा 21 की उपधारा 2 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उन्हें जिला न्यायाधीशों के एक या अधिक उद्धरणों में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाना है। दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जिला न्यायाधीश की अदालत में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं, वह अपने आप में एक वर्गीकृत अदालत नहीं है और वह जिला न्यायाधीश की अदालत का एक अभिन्न अंग है। हालाँकि उसके अधिकार क्षेत्र को धारा 21 की उपधारा 2 में परिभाषित किया गया है। इसे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके पास अधिकार क्षेत्र के केवल दो स्रोत हैं

1 उन मामलों से निपटने और निपटाने का क्षेत्राधिकार जो उच्च न्यायालय के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसके समक्ष रखे गए हैं

2.उन मामलों से निपटने और निपटाने का क्षेत्राधिकार जो जिला न्यायाधीश द्वारा उसे सौंपे गए हैं। इस प्रकार उसके पास सीधे अदालती कामकाज पर विचार करने की कोई शक्ति नहीं है जब तक कि इसे ऊपर बताए गए दो स्रोतों के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। धारा 21 की उप-धारा (3) अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को इस अर्थ में निर्धारित करती है कि, उपरोक्त दो स्रोतों में से किसी एक या दोनों से उसे संदर्भित मामलों से निपटने और निपटाने के दौरान, वह जिला न्यायाधीश का न्यायालय माना जाएगा। इस प्रकार, जिला न्यायाधीश का एक मान्य न्यायालय होने के नाते उसके पास जिला न्यायाधीश के न्यायालय की सभी न्यायिक शक्तियाँ हैं। इस प्रकार धारा की उप-धारा (2) के तहत व्यवसाय के संबंध में उसे जिला न्यायाधीश के न्यायालय का एक काल्पनिक कानूनी दर्जा प्रदान किया जाता है, जो भी उसे सौंपा गया हो। और स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट है कि जब जिले का जिला न्यायाधीश किसी मामले को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को सौंपता है तो वह कोई अन्य जिला न्यायाधीश नहीं बनाता है। इसलिए श्रृंखला को पूरा करने के लिए, यह कहना वैध होगा कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जिला न्यायाधीश के न्यायालय में क्षेत्राधिकार का

प्रयोग करता है और वह जिले के जिला न्यायाधीश द्वारा उसे सौंपे गए किसी भी मामले से निपटेगा और उसका निपटान करेगा। जिला न्यायाधीश के न्यायालय के रूप में माना जाता है। ऐसी स्थिति में, जिले के जिला न्यायाधीश एक न्यायालय के रूप में अपनी पहचान बरकरार रखते हैं, और फिर भी ऐसे न्यायालय का एक मान्य रंग अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को भी प्रदान किया जाता है। सामंजस्यपूर्ण ढंग से समझा जाए तो धारा 21 समग्र रूप से यही प्रावधान करती है।

(8) हालाँकि, धारा 21-ए एक अलग क्षेत्र को कवर करती है। जब मामलों और अपीलों को प्राप्त करने और पंजीकृत करने के कार्यों सहित जिला न्यायाधीश के किसी भी कार्य को एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को सीधे सौंपा जाता है, तो वह जिला न्यायाधीश के समान शक्ति का प्रयोग करता है। लेकिन धारा 21 की उप-धारा (3) के तहत वह न्यायालय के कार्य के केवल उस भाग के लिए जिला न्यायाधीश का न्यायालय माना जाता है जो उच्च न्यायालय के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे प्राप्त होता है या वह कार्य जो उसे सौंपा जाता है। उसे जिला न्यायाधीश द्वारा निपटाए जाने और निपटाए जाने के लिए। धाराओं की यह जोड़ी किसी भी तरह से धारा 20 के तहत एक जिले के एक जिला न्यायाधीश को प्रदान करने के खिलाफ नहीं है। इसे जिला न्यायाधीश का न्यायालय माना जाएगा या जिला न्यायाधीश के समान शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि जिला न्यायाधीश स्वयं जिला न्यायाधीश नहीं है। . और धारा 21 और 21-ए के तहत उन शक्तियों का आनंद ले रहे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश किसी भी तरह से दूसरे जिला न्यायाधीश नहीं बन सकते हैं, जिससे अधिनियम की धारा 20 का उल्लंघन हो। यह स्पष्ट व्याख्या है जो स्वयं को हमारे सामने प्रस्तुत करती है।

(9) प्रस्तावना से पता चलता है कि अधिनियम संलग्न कॉलम में कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को कम करने का एक उपाय है। इसकी धारा 3 में प्रावधान है कि किसी भी कर्मचारी को जांच के अलावा बर्खास्त नहीं किया जाएगा या रैंक में कमी नहीं की जाएगी। उसे अपने विरुद्ध लगे आरोपों के बारे में सूचित किया गया है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है। धारा 4 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि बर्खास्तगी या सेवा से हटाने का जुर्माना तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि इसे निदेशक द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। यहां निदेशक का अर्थ है [जब धारा 2(बी) की सहायता से पढ़ा जाता है] सार्वजनिक निर्देश निदेशक, चंडीगढ़ को अधिनियम के तहत निदेशक के कार्यों को करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एक अन्य अधिकारी को शामिल करना है। धारा 4 की उपधारा (2) में प्रावधान है कि जहां धारा 3 में निर्दिष्ट जांच के बाद बर्खास्तगी या सेवा से हटाने का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है, प्रस्ताव को संबंधित रिकॉर्ड और सूचना के साथ निदेशक को भेजा जाएगा। इस प्रकार संदर्भित प्रस्ताव के बारे में संबंधित कर्मचारी को भी साथ-साथ भेजा जाएगा। धारा 4 की उपधारा (3) कर्मचारी को उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि के भीतर निदेशक को प्रस्तावित दंड के खिलाफ एक अभ्यावेदन देने में सक्षम बनाती है, जो बाद में ऐसा कर सकता है। रिकॉर्ड की जांच करना और लिखित आदेश द्वारा

पक्षों को सुनवाई का अवसर देना, जैसा भी मामला हो, बर्खास्तगी या सेवा से हटाने का प्रस्तावित जुर्माना लगाने के लिए अपनी मंजूरी देना, या यदि ऐसा हो तो मंजूरी देने से इंकार कर देना। प्रस्ताव दुर्भावनापूर्ण या उत्पीड़न के माध्यम से या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से उचित नहीं पाया गया है। धारा 4 की उपधारा (4) एक अपीलीय मंच प्रदान करती है। उप-धारा (2) के तहत निदेशक के आदेश से व्यथित कोई भी पक्ष जिला न्यायाधीश के पास अपील दायर कर सकता है, जो पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। अब इसी प्रावधान के तहत उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 ने जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की है। लोक शिक्षण निदेशक के आदेश के विरुद्ध चंडीगढ़।

10. श्री सिब्बल का तर्क है कि अपील अकेले जिला न्यायाधीश के पास है; यह वह है जिसे पार्टियों को सुनवाई का अवसर देना था; यह वह है जिसे एक आदेश पारित करना था जैसा कि वह उचित समझता था, और उसके पास अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को अपील करने की कोई शक्ति नहीं थी, इस तथ्य के बावजूद कि अपील जिला न्यायाधीश की अदालत में दायर की गई थी और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एक न्यायाधीश था जिसने पंजाब न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत उस जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था। तो सहायक प्रश्न यह है कि जिला न्यायाधीश के न्यायालय में क्या शामिल है? वह खुद अकेला? अथवा, क्या अपर जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जो उस न्यायालय का अभिन्न अंग है, जिसे जिला न्यायाधीश का न्यायालय कार्य सौंपा जा सकता है?

11. अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में प्रावधान है कि जहां धारा 3 में निर्दिष्ट जांच के बाद, रैंक में कमी का दंड लगाने का प्रस्ताव है, कर्मचारी को लगाए जाने के लिए प्रस्तावित शास्ति पर अभ्यावेदन करने का एक तर्कसंगत अवसर दिया जाएगा और कटौती का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक ऐसा अवसर नहीं दिया गया है, तब तक रैंक का पद पारित किया जाएगा। रैंक में कमी के लिए सार्वजनिक निर्देशों के निदेशक के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है जैसे बर्खास्तगी या सेवा से हटाना। रैंक में कमी पर, कर्मचारी अकेले पीड़ित पक्ष है। इसलिए धारा 5 की उपधारा (2) में एक कर्मचारी के लिए अपील का अधिकार बनाया गया है, जो यह प्रदान करता है कि एक कर्मचारी जिसके खिलाफ रैंक में कमी का आदेश पारित किया गया है, निर्धारित अवधि के भीतर और निर्धारित तरीके से, जिला न्यायाधीश को अपील दायर कर सकता है, और जिला न्यायाधीश, रिकॉर्ड की जांच करने और पार्टियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, रैंक में कमी के आदेश को रद्द कर दें यदि यह दुर्भावनापूर्ण या पीड़ित के माध्यम से पाया जाता है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा वारंट नहीं किया

जाता है। धारा 12 राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। धारा 12 की उप-धारा (2) (ii) में प्रावधान है कि ऐसे नियम धारा 5 के तहत जिला न्यायाधीश को अपील दायर करने का तरीका और उस अवधि के भीतर प्रदान कर सकते हैं जिसके भीतर इसे दायर किया जाना है। उसकी उपधारा (3) में यह आदेश दिया गया है कि इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष उसमें अभिकल्पित रीति से अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। पंजाब संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) नियम, 1978 के नियम 7 में अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत अपील के क्षेत्र को शामिल किया गया है। नियमों के नियम 7 के उप-नियम (1) में निम्नानुसार प्रावधान है: -

"(1) धारा 5 की उपधारा (2) के तहत अपील अपीलकर्ता या उसके वकील द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में की जाएगी और आदेश की तारीख के तीस दिनों के भीतर जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की जाएगी। ज्ञापन के साथ उस आदेश की प्रति संलग्न होगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है (जब तक कि अपीलीय न्यायालय उसे समाप्त नहीं कर देता) और उस जांच रिपोर्ट की जिस पर इसकी स्थापना की गई है।

उपनियम (3) में निम्नानुसार प्रावधान है -

"(3) अपीलकर्ता, जिला न्यायाधीश की अनुमति के बिना, अपील के ज्ञापन में उल्लिखित आपत्ति के किसी भी आधार के समर्थन में सुनवाई का आग्रह नहीं करेगा; लेकिन जिला न्यायाधीश, अपील का फैसला करने में; अपील के ज्ञापन में निर्धारित आपत्ति के आधारों तक ही सीमित नहीं होगा या इस नियम के तहत न्यायालय की अनुमति से लिया जाएगा।

12. नियम 7 में "न्यायालय/अपीलीय न्यायालय" शब्दों का 'जिला न्यायाधीश' के साथ परस्पर उपयोग एक स्पष्ट संकेत है कि विधायिका ने 'जिला न्यायाधीश' अभिव्यक्ति का परस्पर उपयोग 'न्यायालय' या जिला न्यायाधीश के 'अपीलीय न्यायालय' के रूप में किया है। अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) के तहत अनुमोदन प्राप्त होने के मद्देनजर नियम 7 प्रकृति में वैधानिक है। यह ऐसा है जैसे अधिनियम के पाठ में नियम 7 शारीरिक रूप से जड़ा हुआ है। इस प्रकार यह कल्पना नहीं की जा सकती है कि जिला न्यायाधीश धारा 5 की उपधारा (2) के तहत अपील के प्रयोजनों के लिए अपीलीय न्यायालय या न्यायालय है और अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए ऐसा

न्यायालय या अपीलीय न्यायालय नहीं है। इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि धारा 4(4) के तहत जिला न्यायाधीश को अपील दायर करने की रीति या इस प्रयोजन के लिए परिसीमा की अवधि निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार की सामान्य शक्ति के तहत अब तक कोई नियम नहीं बनाया गया है। हो सकता है कि विधायिका ने अपने विवेक से अपीलीय मंच को पीड़ित पक्षों के लिए व्यापक रूप से खुला रखने के बारे में सोचा हो, जो सीमा और अभिवचन के नियमों से मुक्त हो, और जिला न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को किसी भी समय पीड़ित पक्षों द्वारा आह्वान किया जा सके। हालाँकि, हमारा मतलब यह नहीं है कि हम इस पहलू पर अंत में उच्चारण करें, क्योंकि यह सीधे तौर पर हमारी चिंता नहीं करता है। तथापि, वर्तमान मामले में हम इस स्तर पर जिस बात पर जोर देते हैं वह यह है कि जिला न्यायाधीश का न्यायालय अपीलीय मंच है और इस प्रकार यह अपील प्राप्त करता है न कि जिला न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के रूप में नामित व्यक्ति। एक बार जब अपील पर विचार किया जाता है और जिला न्यायाधीश की अदालत द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से इस प्रकार है कि जिला न्यायाधीश को न केवल निपटान के लिए अपील को बनाए रखने का अधिकार है, बल्कि पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 21 के तहत अपने न्यायालय में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए राज्य द्वारा नियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को भी देने का अधिकार है उस अपील पर कार्रवाई और निपटान करते समय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश का न्यायालय माना जाएगा। प्रबलित रूप से हम न्यायिक प्राधिकार से रहित उसी दृष्टिकोण पर वापस आते हैं।

13. दूसरी ओर, श्री जेएन कौशल ने तर्क दिया कि एक बार श्री सिब्बल ने स्वीकार किया था कि जिला न्यायाधीश एक अदालत के रूप में अपील करता है, तो पंजाब **जनरल क्लॉज एक्ट और पंजाब कोर्ट एक्ट के प्रावधानों** को पढ़ने पर यह माना जाता है कि अधिनियम में अपीलीय मंच का प्रावधान जिला न्यायाधीश के न्यायालय के पास है, और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को अपील करने के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। दूसरे, उन्होंने कहा कि तथ्यात्मक रूप से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। दूसरे तर्क का विज्ञापन करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि उस वेतन को रिट याचिका का निपटान करने वाली बेंच द्वारा देखा जाना चाहिए। हालांकि, हम श्री कौशल के तर्क से प्रभावित हैं कि अधिनियम का उद्देश्य केवल एक अपीलीय मंच प्रदान करना था और अपीलीय निर्णय केवल जिला न्यायाधीश के व्यक्ति तक ही सीमित

नहीं था। कानून की नजर में, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जो अपील करने पर जिला न्यायाधीश की अदालत में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, अपील के लिए जिला न्यायाधीश के रूप में अच्छा है।

14. महत्वपूर्ण रूप से, कानून के एक सामान्य प्रस्ताव को बताते हुए, **मेन अब्दुल अज़ीर बनाम पंजाब सरकार** () 1977 पीएलजे 375 **में लाहौर उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 16** की व्याख्या करते हुए **कहा कि जब एक** न्यायालय में सामान्य रूप से एक न्यायिक अधिकारी होता है, जैसा कि एक जिला न्यायाधीश की अदालत करती है (तब अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत को अलग से वर्गीकृत किया गया था) यह काफी सामान्य प्रथा है भारतीय संविधियों के प्रारूपण में उस अधिकारी को उसके विशेष शीर्षक के तहत संदर्भ देने के लिए और न्यायालय को संदर्भित करने का इरादा है और इसलिए जिला न्यायाधीश के संदर्भ और जिला न्यायालय के संदर्भ के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है ताकि यह तय किया जा सके कि क्या संदर्भित प्राधिकारी न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा था। उस आचरण में यह माना गया था कि उच्च न्यायालय के पास धारा 16 के तहत जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका पर विचार करने की शक्ति थी।

अब मिलिटेटिंग केस लॉ पर।

15. गुरु गोबिंद सिंह रिपब्लिक कॉलेज, जंडियाला के मामले (सुप्रा) की प्रबंध समिति में, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक अलग दृष्टिकोण लिया। यह मामला वर्तमान अधिनियम के तहत उत्पन्न हुआ। वहां निदेशक ने कर्मचारी को हटाने की मंजूरी नहीं दी। निदेशक के आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 4(4) के तहत प्रबंधन की अपील जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर की गई थी, जिन्होंने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को अपील सौंपी। अपील की अस्वीकृति पर, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के अपीलीय आदेश को इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी और इसने यह विचार किया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास अधिनियम के तहत अपील को सुनने और तय करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। एक शाब्दिक निर्माण 'जिले के जिला न्यायाधीश' अभिव्यक्ति के लिए रखा गया था। रिट याचिका के तरीके को निम्नानुसार देखते हुए अनुमति दी गई: -

"..... इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिला न्यायाधीश द्वारा उसे सौंपे गए मामले का निपटारा करते समय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश का न्यायालय माना जाएगा, लेकिन तर्क के

किसी भी खिंचाव से यह नहीं माना जा सकता है कि ऐसे मामलों का निपटान करते समय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को जिले का जिला न्यायाधीश माना जाएगा। पंजाब कोर्ट एक्ट की धारा 20 के तहत जिले का सिर्फ एक ही जिला जज हो सकता है। यदि प्रतिवादियों के लिए विद्वान वकील का तर्क उस मामले में प्रबल होता है, तो यह अनुसरण करेगा कि पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 20 के तहत नियुक्त जिला न्यायाधीश के अलावा , अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, उस जिले के जिला न्यायाधीश भी होंगे। इस तरह की व्याख्या धारा 20 के प्रावधान की भाषा का उल्लंघन करती है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि जिले का केवल एक जिला न्यायाधीश हो सकता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

16. उचित सम्मान के साथ, उक्त मामले में बीएस ढिल्लों और जीसी मित्तल, जेजे द्वारा व्यक्त किए गए विचार बहुत संकीर्ण थे। अधिनियम केवल एक अपीलीय मंच और एक न्यायिक सीट से एक अपीलीय निर्णय प्रदान करता है। इस मामले पर विचार करने के बावजूद हम जिला न्यायाधीश, जो स्पष्ट रूप से जिले के लंबे जिला न्यायाधीश हैं, के व्यक्ति में निहित अपीलीय शक्ति को सीमित करने में कोई राशन योग्य नहीं पाए हैं। डिवीजन बेंच के विचार इस तरह से आधारित प्रतीत होते हैं जैसे कि अपील व्यक्तिगत रूप से जिला न्यायाधीश के पास थी। यदि न्यायपीठ को यह सलाह दी गई होती कि जिला न्यायाधीश का केवल एक न्यायालय है, मूल क्षेत्राधिकार का प्रधान न्यायालय है, और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, यदि नियुक्त किया जाता है, तो वह उस न्यायालय का अभिन्न अंग है और माना जाता है कि उसे सौंपे गए कार्य के लिए न्यायालय में जिला न्यायाधीश है, तो शायद यह दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता था। यह संविधियों की व्याख्या का एक हितकारी नियम है कि न्यायालयों को उनके विभिन्न उपबंधों की इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिए ताकि उनमें सामंजस्य स्थापित किया जा सके और अधिनियम के उपबंधों में किसी भी असंगति से बचा जा सके। पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 20 और 21 को एक साथ पढ़ा जाना था और इसलिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को समाप्त करने से बचने के लिए व्याख्या की जानी थी। अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि विधायिका ने केवल जिला न्यायाधीश के रूप में अपीलीय मंच उपलब्ध कराने में उत्साह दिखाया हो। बल्कि हमारा विचार है कि अपीलीय मंच जिला न्यायाधीश के न्यायालय में प्रदान किया गया था, जिसमें से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एक हिस्सा और पार्सल है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को किसी भी स्थिति में जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए

निर्णय की तुलना में गुणवत्ता और प्रभावकारिता में कम नहीं कहा जा सकता है। हमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को समाप्त करने के लिए अधिनियम में कोई सामग्री नहीं मिलती है, खासकर जब **पंजाब न्यायालय अधिनियम** न्यायिक शब्दों में ऐसा अंतर नहीं करता है। इसलिए हमारे पास प्रबंध समिति के मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

17. याचिकाकर्ता के लिए उद्धृत एक अन्य डिवीजन बेंच का निर्णय **मंगल राम बनाम चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र** 1977 **पी.एल.जे 375,** सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत उपद्रवियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 **के तहत उपयोग** किया गया था। वहां भी वही दृष्टिकोण ए. एस. नरूला, सी. जे. और पी. सी. जैन, जे. (जैसा कि तब उनका लॉर्डशिप था) लिया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन अपीलीय अधिकारी, जो उस जिले का जिला न्यायाधीश होगा या उस जिले का ऐसा अन्य न्यायिक अधिकारी होगा जो जिला न्यायाधीश के रूप में पदाभिषेक नहीं करेगा, इस निमित्त नामजद कर सकेगा। उक्त अधिनियम की धारा 9 के संदर्भ में इस प्रकार टिप्पणी की गई है-

"6. अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि अपील एक अपीलीय अधिकारी को दी जाती है जो उस जिले का जिला न्यायाधीश होगा या उस जिले में ऐसा अन्य न्यायिक अधिकारी होगा जो 10 वर्ष से कम नहीं है। वर्तमान मामले में श्री आनंद स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा बार में यह बहुत ही निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया गया था कि अधिनियम की धारा 9 के तहत परिकल्पित अपील को सुनने के लिए जिला न्यायाधीश द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को नामित नहीं किया गया था।

18. पंजाब न्यायालय अधिनियम की धाराओं और 21 **के बल पर वैकल्पिक तर्क,** अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र के लिए याचिका को खारिज करते हुए, वही दृष्टिकोण लिया गया था। यह निम्नानुसार देखा गया था: -

"..... इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि मामलों का निपटान करते समय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश का न्यायालय माना जाएगा, लेकिन तर्क के किसी भी खिंचाव से यह नहीं माना जा सकता है कि मामलों का निपटान करते समय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को जिले का जिला न्यायाधीश माना **जाएगा। पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 20 के तहत,** जिले का केवल एक जिला न्यायाधीश हो सकता है। यदि प्रतिवादी के विद्वान वकील के तर्क को कुछ तार्किक अंत

तक ले जाया जाता है तो इसका परिणाम यह होगा कि धारा 20 के तहत नियुक्त जिला न्यायाधीश के अलावा, **पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 21** के तहत नियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भी उस जिले के जिला न्यायाधीश होंगे। इस तरह की व्याख्या न तो प्रशंसनीय है और न ही क़ानून के प्रासंगिक प्रावधानों से कटौती योग्य है।

19. यहां फिर से, डिवीजन बेंच द्वारा व्यक्त किए गए विचार, उचित सम्मान के साथ, संदर्भ में संकीर्ण हैं और उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। पहले के मामले की तरह ही तर्क के लिए, हमें पूर्वोक्त कानून के प्रस्ताव को रद्द करना होगा, जो **पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 20 और 21 की** संकीर्ण रूप से व्याख्या करता है जैसे कि अपील जिले के जिला न्यायाधीश के एकमात्र व्यक्ति के लिए है।

20. बार में उद्धृत अन्य मिसालें कम महत्व की हैं। पक्षकारों के विद्वान वकील के प्रति निष्पक्ष होने के लिए, हम उन्हें नोट करेंगे।

21. **केरल राज्य विद्युत बोर्ड, त्रिवेंद्रम बनाम टीपी कुन्हलीम्मा** (1976) 4 एससीसी 634, **एआईआर 1977 एससी 282 में**, सुप्रीम कोर्ट ने वही दृष्टिकोण लिया जो मियां अब्दुल अजीज के मामले (सुप्रा) में लिया गया था और कहा गया था कि **टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 10 और 16 के प्रावधानों के तहत**, जिला न्यायाधीश न्यायालय के रूप में न्यायिक रूप से कार्य करता है और यह कि कई संविधियों में जब इस विशेष शीर्षक के तहत जिला न्यायाधीश को संदर्भ दिया जाता है, तो इरादा जिला न्यायाधीश के न्यायालय को संदर्भित करना होता है। जिला न्यायालय के लिए जो लागू परिभाषा द्वारा निहित अर्थ प्रतीत होता है।

22. **सेंट्रल टॉकीज लिमिटेड, कानपुर बनाम द्वारका प्रसाद** () एआईआर 1961 एससी 606 में, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के दोनों न्यायाधीशों के विचारों की पुष्टि की। विशेष रूप से, बृज मोहन लाल, जे के विचारों की पुष्टि की गई थी, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि जिला मजिस्ट्रेट ने मामले को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करके उन्हें **उत्तर प्रदेश (अस्थायी) किराया और बेदखली नियंत्रण अधिनियम, 1947** के तहत अपने कार्यों का प्रदर्शन करने के लिए अधिकृत किया था, क्योंकि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को **धारा 2 (घ)** इसके अलावा, जो निष्कासन के लिए मुकदमा दायर करने की अनुमति देने के लिए सक्षम था। परोक्ष रूप से यह निर्णय श्री सिब्बल द्वारा उद्धृत के माध्यम से प्रतिवादी के मामले का समर्थन करता है।

23. **रामचन्द्र अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** () एआईआर 1966 एससी 1888 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया **कि निर्णय के लिए एक सिविल कोर्ट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 (1)** के तहत एक संदर्भ एक व्यक्ति पदनाम का संदर्भ था और माना कि सिविल **प्रक्रिया संहिता की धारा 24 का प्रावधान,** ऐसे संदर्भ के मामले में जिला न्यायाधीश को मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरित करने की अनुमति देना उपलब्ध था।

24. **एलआरएस द्वारा ठाकुर दास (मृत) में। मध्य प्रदेश राज्य** () (1978) 1 एससीसी 27, एआईआर 1978 एससी 1, **न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जब सत्र न्यायाधीश को** आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 सी के तहत राज्य सरकार **द्वारा अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया था, तो राज्य सरकार ने** जो किया वह सत्र न्यायालय में एक अपीलीय प्राधिकरण का गठन करना था, जिस पर सत्र न्यायाधीश ने अध्यक्षता की थी।

25. सुप्रीम कोर्ट के इन सभी फैसलों में अंतर्निहित तनाव, जिसमें टीपी कुन्हलीम्मा के मामले (सुप्रा) में एक भी शामिल है, इस आशय का है कि जब जिला या सत्र न्यायाधीश को किसी मामले का फैसला करने की शक्ति प्रदान की जाती है, तो इसका मतलब उसे एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि उसके न्यायालय में प्रदान करना है जिसकी वह अध्यक्षता करता है। और यदि ऐसा है, तो सभी आवश्यक परिस्थितियों के साथ-साथ कानून के तहत अनुमति के अनुसार न्यायालय के कार्य को डायवर्ट करने और बनाने या असाइनमेंट करने का पालन किया जाता है, जिसके द्वारा न्यायालयों का गठन किया जाता है। हमें अन्य उच्च न्यायालयों से उपलब्ध केस लॉ के साथ निर्णय को बोझिल करने की आवश्यकता नहीं है।

26. निष्कर्ष निकालने के लिए, हम निम्नानुसार हैं:

(क) अपर जिला न्यायाधीश पंजाब संबद्ध महाविद्यालय (कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1974 की धारा 4 की उपधारा (4) के **अधीन अपील का विनिश्चय करने के लिए पूर्णत सक्षम है,** यदि जिला न्यायाधीश द्वारा उस पर कार्रवाई किए जाने और उसका निपटान करने के लिए अपील की जाती है। और यह अधिकार क्षेत्र के प्रश्न का हमारा उत्तर है;

(ख) किसी जिले में जिला न्यायाधीश के न्यायालय में प्रथमतः जिला न्यायाधीश का व्यक्ति और तत्पश्चात् अपर जिला न्यायाधीश/न्यायाधीश शामिल होते हैं, जिन्हें अपने न्यायालय में अधिकारिता

का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया जाता है, ऐसे न्यायालय कार्य के लिए जो केवल उसे या उन्हें सौंपे गए हैं और जिला न्यायाधीश के न्यायालय के रूप में माने जाते हैं, उनके द्वारा निपटाए गए और निपटाए जाते हैं। यह न्यायिक प्रभावोत्पादकता के लिए है न कि दूसरा जिला न्यायाधीश बनाने के लिए। यह सहायक प्रश्न का हमारा उत्तर है; और

(ग) यहां पहले दर्ज किए गए कारणों के लिए, हम प्रबंध समिति के मामले और मंगल राम के मामले (सुप्रा) में व्यक्त विचारों को खारिज करते हैं, जहां तक वे अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते समय पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 20 और 21 की व्याख्या से संबंधित हैं।

उपरोक्त तरीके से उल्लिखित बिंदु को निर्धारित करने के बाद, हम मामले को कानून के अनुसार निपटान के लिए डिवीजन बेंच को वापस भेजते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्ण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयर्ण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुकत रहेगा ।

Checked By:

Deepak yadav

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy

Chandigarh